

Nutritious food should be promoted via PPP mode, says ASSOCHAM

● AGENCIES
New Delhi

With India and its agriculture and food processing sectors facing grave nutritional challenges, industry lobby The Associated Chambers of Commerce of India (ASSOCHAM), on Sunday, suggested that the government must adopt a two-pronged strategy based on the public-private partnership (PPP) route to promote nutritious and diversified food production.

In a report, "Bridging the gap: Tapping agriculture potential for optimum nutrition", jointly prepared with British financial services firm Ernst & Young (EY), Assocham said that while the government in partnership with companies should promote nutritious food among consumers, it should also promote diversified and resilient food production to reduce

costs. "There is a need to focus on a dual pronged approach, where on the demand side, nutritious food is promoted among consumers by bringing companies and the government together on a consumer sensitisation campaign; and on the other hand, diversified and resilient food production is promoted that reduces the cost of production on the supply side," it said.

"India must bring about both policy and practice level reforms in order to cater to the large unmet need of both macronutrients and micronutrients." The nutrition and agriculture programs will need to strengthen both demand and supply side initiatives such as agricultural diversification of farmland, food production, food fortification, strengthening food supply chains, empowering local communities for growing nutritious food and en-

couraging kitchen gardens," Assocham said.

India needs to shift its approach towards "responsible farming" where enhancing agricultural production can no longer be seen as the sole objective of the sector, according to the Assocham-EY study.

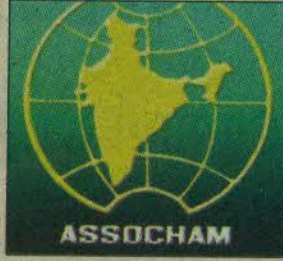
"Focusing on nutritional adequacy to address India's malnutrition crisis will have to be considered as a prime objective as the country is home to about 50 per cent of world's undernourished children," it said. The study also suggested the need to shift focus to a "crop-neutral agricultural policy" that reduces the bias toward particular staple commodities while encouraging farmers to respond to the market demands.

According to Assocham, "bio-fortification" would prove to be a more effective strategy in India as it is cost-effective and has the ability to reach the rural population.

'पौष्टिक व विविध खाद्य उत्पादन को दें बढ़ावा'

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर (एजेसिया)। देश को कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एसोचैम-ईवाई की संयुक्त रिपोर्ट में यह सलाह दी गई है कि भारत को पौष्टिक, विविध और लोचदार खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर दो-आयामी रणनीति बनानी चाहिए।

एसोचैम और वैश्विक पेशेवर सेवा फर्म ईवाई (अर्नेस्ट एंड यंग) के संयुक्त अध्ययन अंतराल को कम करना सर्वोत्कृष्ट पोषण के लिए कृषि क्षमता का दोहन में कहा गया, एक दो-आयामी दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जहां मांग पक्ष पर, कंपनियों और सरकारों को एक साथ आकर उपभोक्ता संवेदनशीलता अभियान चलाना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं के बीच पोषक भोजन को बढ़ावा



■ एसोचैम-ईवाई की संयुक्त रिपोर्ट दी गई सलाह

दिया जा सके, और वहीं दूसरी तरफ विविध और लोचदार खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि आपूर्ति पक्ष की तरफ उत्पादन की लागत में कटौती हो। रिपोर्ट में कहा गया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की बड़े पैमाने पर पूरी नहीं हुई जरूरत को देखते हुए भारत को नीतिगत और अभ्यास स्तर पर सुधार करने की जरूरत है, जो यह लोगों को कम कीमत पर पौष्टिक

पौष्टिकता व कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को मजबूत करना होगा, जिसमें खेत में कृषि का विविधीकरण, खाद्य उत्पादन, खाद्य सुदृढीकरण, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करना, पौष्टिक भोजन उगाने के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और किचन गार्डन को बढ़ावा देना शामिल है : एसोचैम

भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करे। रिपोर्ट में कहा गया, पौष्टिकता व कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को मजबूत करना होगा, जिसमें खेत में कृषि का विविधीकरण, खाद्य उत्पादन, खाद्य सुदृढीकरण, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करना, पौष्टिक भोजन उगाने के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और किचन गार्डन को बढ़ावा देना शामिल है। एसोचैम-ईवाई के अध्ययन में यह भी कहा गया कि संतुलित और विविध आहार के महत्व को लेकर समुदाय के बीच जागरूकता फैलाना, और उन्हें

सशक्त बनाना, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि वे स्वयं और उनके परिवारों के लिए स्मार्ट पोषण विकल्प चुन सकें। इस रिपोर्ट में 'जिम्मेदार खेती' के बारे में भारत के दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि कृषि उत्पादन को बढ़ाना अब इस क्षेत्र के एकमात्र उद्देश्य के रूप में नहीं देखा जा रहा है। भारत के कुपोषण संकट को हल करने के लिए पोषण संबंधी पर्याप्तता पर ध्यान केंद्रित करना देश का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यहां दुनिया के 50 फीसदी से ज्यादा कुपोषित बच्चे रहते हैं। एसोचैम-ईवाई अध्ययन में यह भी कहा कि फसल-तटस्थ कृषि नीति में बदलाव की जरूरत है, जो विशेष रूप में मुख्य वस्तुओं के खेती की तरफ झुकाव पैदा करता है और किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

सभी को मिले पोषक भोजन

नई दिल्ली। देश में लोगों को सस्ते पोषक खाद्य पदार्थों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नीति एवं व्यावहारिक स्तर पर सुधार की दिशा में काम करना होगा। उद्योग मंडल एसोचैम और ईवाई की संयुक्त रिपोर्ट में यह कहा गया है। इसमें कहा गया है कि देश में कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में गंभीर पोषण संबंधी चुनौतियाँ हैं। रिपोर्ट में दो स्तरीय रणनीति का सुझाव देते हुए कहा गया है कि कंपनियों तथा सरकार की तरफ से ग्राहकों के बीच पोषक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसमें सूक्ष्म तथा अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए कहा गया है, देश को नीति एवं व्यावहारिक स्तर पर सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है जिससे कम लागत पर पोषक खाद्य पदार्थों की आसान पहुंच सुनिश्चित हो।